हिन्दी दैनिक

इंडिया वार्ता

R.N.I NO. UTTHIN/2011/39104

सच के साथ-जन के साथ

लोकतंत्र में जनसरोकार का सशक्त माध्यम

आत्मिक वाणी

मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना अपने मन मे मेरी बातों को याद रखना क्योकि ऐसा करने से तेरे जीवन के दिन और तेरे वर्ष और बढ़ेगे। तेरा अधिकाधिक कल्याण ही होगा मेरे पुत्र करूणा और सच्चाई कभी तुझ से अलग ना हो तू उनको अपने गले का हार बना कर रखना और उनकों अपने हृदय पटल पर लिख लेना तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में कृपा का पात्र होगा।

प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपनी .. 8

वर्ष : 14 अंक : 258 | देहरादून, मंगलवार 13 मई 2025 | शुल्क : पचास पैसे | पृष्ठ संख्या : 08

मुख्यमंत्री ने डोल आश्रम में श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम न्यास के श्री पीठम स्थापना महोत्सव कार्यक्रम में किया प्रतिभाग

आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा मानसखंड मंदिर माला मिशन : मुख्यमंत्री

इंडिया वार्ता ब्यूरो

अल्मोड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को लमगड़ा, अल्मोड़ा स्थित डोल आश्रम में श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम न्यास के श्री पीठम स्थापना महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने 1100 कन्याओं का पूजन किया , माँ राजेश्वरी का अभिषेक तथा पूजा-अर्चना कर देश व प्रदेश की सुख समृद्वि की कामना की।

मुख्यमंत्री ने पहलगाम हमले पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहा है। हमारे सुरक्षाबलों ने इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा डोल आश्रम में आकर उन्हें हमेशा दिव्य ऊर्जा का अहसास होता है। बाबा कल्याणदास जी महाराज ने आश्रम में जिस प्रकार से श्रीयंत्र स्थापित किए हैं, वो आने वाले समय में भारतवर्ष के साथ सम्पूर्ण विश्व के लिए श्रद्धा का केंद्र बनेगा एवं इस आश्रम में शान्ति, आध्यात्म और संस्कृति को जानने के लिए विश्वभर से लोग आयेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मानसखंड मंदिर माला मिशन के माध्यम से समस्त मंदिरों को अवस्थापना सुविधाओं से जोड़ रही है , ताकि आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा डोल आश्रम, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ युवाओं को भारतीय संस्कृति के बारे में शिक्षित करने का महान कार्य कर रहा है। हमारे जैसे सांस्कृतिक प्रदेश जहॉ पर इतने देवस्थान है इस भूमि में जन्म लेना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है, यह आश्रम हमारी पुरानी सभ्यता, संस्कृति का जीती-जागती उदाहरण और मिशाल है। यह साधना और आध्यात्म का भव्य और दिव्य केन्द्र है। उन्होंने कहा राज्य सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड को विकल्प रहित संकल्प के ध्येय के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सनातन संस्कृति की पताका सम्पूर्ण विश्व में लहरा रहा है। उन्होंने कहा प्रदेश में संस्कृति संरक्षण हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्व

– शेष पृष्ठ 7 पर ..

लाटू में आयोजित कार्यक्रम सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि यह आस्था, परम्परा और एकता का प्रतीक: मुख्यमंत्री

लाटू धाम में दर्शनों के दौरान भारतीय सेना के शौर्य का भी मुख्यमंत्री ने किया अभिनन्दन

इंडिया वार्ता ब्यूरो

चमोली । चमोली के वांण गांव में सोमवार को पूजा अर्चना के बाद विधि विधान से सिद्धपीठ लाटू मंदिर के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लाटू धाम पहुंचकर पूजा-अर्चना कर देश और राज्य की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। उन्होंने कपाट खुलने के अवसर पर लाटू धाम पहुंचे सभी श्रद्धांलुओं का स्वागत और अभिनन्दन किया।

मुख्यमंत्री ने लाटू मंदिर में पूजा अर्चना के बाद आयोजित सभा का आगाज मां नंदा और लाटू देवता के जयकारे के साथ किया। इस दौरान उन्होंने पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना की ओर से की गई कार्रवाई के लिए सैनिकों का अभिनंदन किया। कहा कि उत्तराखण्ड में चार धाम के साथ-साथ तुंगनाथ, रुद्रनाथ, जागेश्वर, आदि कैलाश आदिबद्री जैसे अनेकों महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। इसके साथ ही राज्य के छोटे-छोटे मंदिर राज्य की सांस्कृति परम्पराओं का संरक्षण करते हैं। मुख्यमंत्री ने लाटू धाम के ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व की सराहना करते हुए कहा कि यह मंदिर हमारे हजारों वर्ष पुरानी परंपरा का प्रतीक है आज का यह कार्यक्रम केवल धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि यह आस्था, परम्परा और एकता का प्रतीक है। कहा कि लाटू धाम के मंदिर में आँखों में पट्टी बांध कर दर्शन करने कि परम्परा यह दर्शाती है कि आस्था सिर्फ आंखों से ने बल्कि हृदय से होती है। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड को भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहते है। जिसके लिए

– शेष पृष्ठ 7 पर ..

सीएम ने डॉ. के. विक्रम राव के निधन पर शोक व्यक्त किया

देहरादून, इंडिया वार्ता ब्यूरो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ पत्रकार और इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. के. विक्रम राव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि के विक्रम राव पत्रकारिता जगत की एक सशक्त आवाज थे। उनका योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने भी के विक्रम राव के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

उत्तराखंड में नशाबंदी लागू की जाए : उक्रांद

देहरादून (इंडिया वार्ता ब्यूरो)। उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश में नशाबंदी लागू करने की मांग की है। दल ने कहा कि उत्तराखंड को तत्काल ड्राइ स्टेट घोषित किया जाए। ऐसा नहीं करने पर नशाबंदी आंदोलन की चेतावनी दी है। सोमवार को दल की केंद्रीय महामंत्री किरन रावत ने केंद्रीय कार्यालय में प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल संपूर्ण प्रदेश में नशाबंदी लागू करने का पक्षधर है। हम केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि वह प्रदेश में तत्काल प्रभाव से शराबबंदी/ नशाबंदी लागू कर दे। उन्होंने कहा कि दल जल्दी ही इसे लेकर आंदोलन करेगा। पहले चरण में जागरूकता रैलियां, चेतावनी रैलिया निकाली जाएंगी। उन्होंने कहा कि देहरादून की गलियों में नशे का कारोबार चरम पर पहुंच गया है, जिस कारण कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। महानगर अध्यक्ष विजेंद्र रावत ने कहा कि दल 15 मई से पटेलनगर से रैलियों की शुरुआत करेगा। इसके बाद पूरे शहर में कार्यक्रम होंगे। उन्होंने आंदोलन में जनता से भी सहयोग का आह्वान किया है।

सम्पादकीय

मोदी सरकार के साथ खड़ा है देश और विपक्ष

पाक ने भारत के दिल कश्मीर पर हमला कर के भारत के दिल को चोट पहुचाने की कोशिश की है उसने अप्रैल माह में 28 सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया था उसके बाद दोनो देशों में स्थति तनाव पूर्ण है दोनों देश आमने - सामने आ गये है भारत के पास सेना की बड़ी शक्ति और अत्याआधुनिक हथियार है जो पाकिस्तान के पास नही है जो देश अपने देशवासियों को दो वक्त की रोटी ना दे सके वो भला युद्ध के बारे में सोच भी कैसे सकता है पाक का जैसा नाम पाक है वैसा उसका काम नही है उसने हिन्द को ललकारा है उसका जवाब केन्द्र सरकार के तत्वाधन में सेना ने उसके बैस कैम्प को तबाह कर के करारा जवाब दिया है भारत वहां के किसी भी नागरिक को नुकसान नही पहुचाना चाहता भारत का केवल एक ही लक्ष्य है आंतकवाद को जन्म देने वालों को पनहा करना ही केवल मुख्य उदेदश्य है केन्द्र की मोदी सरकार सेना के संग संग है और हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार भी है लेकिन भारत पहल कभी नही करता लेकिन अपना बचाव तो करेगा ही ना उसी बचाव को करते हुए भारतीय सेना ने हमले किये है और आंतक का पर्याय बने पाक को सबक सिखाया जो बेहद आवश्यक था मोदी सरकार बड़ी सावधानी और कूटनीति के साथ जवाब दे रही है ।

फिर आएगा गौरी: इतिहास के पन्नों से वर्तमान तक का सबक

(क्या पाकिस्तान के साथ भी हम वही भूल दोहरा रहे हैं ?)

-प्रियंका सौरभ

आज़ादी के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कई बार समझौते और संघर्षविराम की कोशिशें की हैं, लेकिन पाकिस्तान की नीतियाँ और उसके आक्रमणों का कोई अंत नहीं आया। यह वही गलती है, जो पृथ्वीराज चौहान ने की थी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को एक बार पराजित किया और उसे जीवनदान दिया, जो बाद में उनके साम्राज्य के पतन का कारण बना। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि शत्रु के प्रति दया और माफ़ी की आदत दीर्घकालिक रूप से हानिकारक हो सकती है।

इतिहास की गलती-पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी को हराया और जीवनदान दिया। लेकिन 1192 में, गौरी ने फिर हमला किया और चौहान को हराकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल बदल दिया। क्या हम भी आज बार-बार माफ़ी देकर वही भूल दोहरा रहे हैं?

इतिहास अपने आप में एक जीवंत कथा है, जो समय-समय पर हमें चेतावनी देता है। इसे नज़रअंदाज़ करने की भूल, एक सभ्यता के पतन की सबसे बड़ी वजह बनती है। पृथ्वीराज चौहान का उदाहरण इसका एक सटीक प्रमाण है। बार-बार की गई माफ़ी और शत्रु पर दया दिखाने की भूल ने एक साम्राज्य को समाप्त कर दिया। यह केवल मध्यकालीन भारत की गाथा

नहीं है, बल्कि आज के दौर में भी यह संदर्भ उतना ही प्रासंगिक है।

पृथ्वीराज चौहान: एक वीर राजा की भूलइतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, अपनी वीरता और अदम्य साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई युद्धों में अद्वितीय पराक्रम दिखाया, लेकिन जब बात मोहम्मद गौरी की आई, तो उनकी माफ़ी देने की प्रवृत्ति ने उन्हें भारी नुकसान पहुँचाया। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में चौहान ने गौरी को पराजित किया और जीवनदान देकर एक गंभीर भूल की। अगले ही वर्ष, 1192 में गौरी ने फिर हमला किया और इस बार चौहान को हराने में सफल रहा। यह वह पल था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया।

इतिहास की पुनरावृत्ति- क्या हम फिर से वही भूल कर रहे हैं?अगर हम अपने वर्तमान हालात पर नज़र डालें, तो क्या हम भी उसी भूल की ओर बढ़ रहे हैं? बार-बार की माफ़ी, नरमी और गलतियों से सबक न लेने की आदत हमें कमजोर बना रही है। चाहे वह सीमा सुरक्षा का मामला हो, या फिर आंतरिक सुरक्षा की चुनौती, हर बार की चुप्पी, समझौते और क्षमादान हमें कमजोर बना रहे हैं।

क्या पाकिस्तान के साथ भी हम वही भूल दोहरा रहे हैं?आज का भारत भी बार-बार पाकिस्तान के साथ उसी भूल का शिकार होता नज़र आ रहा है। बार-बार की गई शांति वार्ताएँ, संघर्षविराम समझौते, और आतंकवाद के हर वार को क्षमा करना क्या हमें फिर से एक कमजोर राष्ट्र की छवि नहीं दे रहा? पाकिस्तान, जो बार-बार हमारी सीमाओं पर हमला करता है, हमारे सैनिकों पर कायराना हमले करता है, और हमारे नागरिकों के खिलाफ आतंकी गतिविधियाँ प्रायोजित करता है, क्या उसे बार-बार माफ़ करना उचित है? क्या हमें इस बात का अहसास नहीं है कि जैसे गौरी ने चौहान की सहिष्णुता का गलत फायदा उठाया, वैसे ही पाकिस्तान भी हमारी हर माफ़ी और नरमी को कमजोरी समझ सकता है?

यह केवल सीमा पर गोलीबारी या आतंकी हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि कूटनीतिक मंचों पर भी हम बार-बार शांति और समझौते की बात करते हैं, जबकि दूसरी ओर से विश्वासघात और आक्रमण की नीति जारी रहती है। यह हमारी सहनशीलता और शांति की भावना का अपमान है, जिसे बार-बार नज़रअंदाज़ करना एक गंभीर भूल हो सकती है।

अमेरिका की छाया में खड़ा पाकिस्तानअमेरिका का रुख भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इतिहास गवाह है कि कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर समर्थन दिया, चाहे वह सैन्य सहायता हो या वित्तीय मदद। अमेरिका ने कई बार पाकिस्तान को अपने भू-राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल किया, जबकि पाकिस्तान ने उस समर्थन का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया। यह हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करता है - क्या हमें बार-बार माफ़ करने की नीति पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए?

पाकिस्तान, जो आतंकवाद का सबसे बड़ा निर्यातक है, उसकी सैन्य और आर्थिक सहायता करने वाला अमेरिका, क्या भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ नहीं है? क्या यह समय नहीं आ गया है कि हम अपनी विदेश नीति को और अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि हमें किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर न रहना पड़े?

इतिहास हमें सिखाता है कि अगर हम अपने शत्रुओं की मंशा को बार-बार नज़रअंदाज़ करेंगे, तो हमें फिर से उसी त्रासदी का सामना करना पड़ेगा जो पृथ्वीराज चौहान ने की थी। माफ़ी की आदत हमें वीर से विवश बना सकती है, और समझौते की कमजोरी हमारे गौरव को मिटा सकती है। समय आ गया है कि हम अपने इतिहास से सबक लें और अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि मानें। माफ़ी एक आदर्श हो सकती है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय सम्मान और स्वाभिमान की हो, तब हमें पाषाण की तरह अडिग और लोहे की तरह कठोर होना पड़ेगा। यही संदेश इस कविता में छिपा है - माफ़ी की जगह पराक्रम, और समझौते की जगह संकल्प। अमेरिका ने पाकिस्तान को कई बार समर्थन दिया है, जबकि पाकिस्तान ने इस समर्थन का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों में किया। यह एक और उदाहरण है कि कैसे बाहरी शक्ति हमारे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम कर सकती है, और हमें अपनी नीति को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। भारत को अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और शत्रु के सामने कठोर और अडिग रहना चाहिए। माफ़ी की जगह पराक्रम और समझौते की जगह संकल्प हो, ताकि हम भविष्य में ऐसे ही संकटों से बच सकें।

जिम्मेदार कौन ?

प्रिय पाठकों आप भी एक पत्रकार हो तथा **दैनिक इंडिया वार्ता** की आवाज बन सकते हैं। बस आपको इसके लिए जरूरत है कि हर समय अपनी आंख व कान खुली रखें। चौंकन्ने रहें कि आपके चारों ओर क्या कुछ घटित हो रहा है। नाबालिग बच्चे ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं? स्कूल बंक कर रहे हैं? विकास कार्यों में गड़बडी हो रही है? निर्माण कार्य महीनों से अधूरे पड़े हैं, पाइप लाइन टूटी हैं, घरों में दूषित पेयजल आपूर्ति या महिनों से पानी नहीं आ रहा है। मनरेगा में धांधली हो रही है? आपकी इस प्रकार की समस्याओं को **दैनिक इंडिया वार्ता** जिम्मेदार कॉलम में प्रमुखता के साथ उठाएगा? बस आप उठाइए कलम और तुरंत लिखकर हमें भेजें या फिर संपर्क करें? आपकी आवाज को सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों एवं सम्बन्धित अधिकारी तक पहुंचाया जाएगा तथा इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल कराने का प्रयास भी किया जाएगा।

संपर्क करें
संपादक
दैनिक इंडिया वार्ता
प्रधान कार्यालय : मोहक्कमपुर खुर्द पोस्ट आई.आई.पी. रेलवे क्रसिंग हरिद्वार रोड़ देहरादून (उत्तराखण्ड)
मोबाईल न.- 7500581414,9359555222
Email: indiawarta@gmail.com

'प्रशासन जनता के द्वार': देहरादून के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में डीएम बंसल का विशेष शिविर, एक छत के नीचे 24 विभागों की सुविधाएं

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून । देहरादून जनपद के अंतिम छोर पर स्थित चकराता के सुदूरवर्ती गांवों में रहने वाले जनमानस की समस्याओं का त्वरित समाधान करने और उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में 14 मई 2025 को एक वृहद बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लाखामण्डल स्थित अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में सुबह 11 बजे से यह शिविर %प्रशासन जनता के द्वार% की अवधारणा को साकार करेगा।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस शिविर का मूल मंत्र अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसी लक्ष्य के साथ 24 विभागों के अधिकारी एक ही छत के नीचे मौजूद रहेंगे, जहां जनमानस की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा और योजनाओं के आवेदन की सभी औपचारिकताएं तुरंत पूरी की जाएंगी।

इस शिविर में स्वास्थ्य जांच से लेकर आयुष्मान कार्ड बनवाने तक, पेंशन संबंधी मामलों से लेकर विभिन्न विभागों के प्रमाण पत्र बनवाने तक, किसान क्रेडिट कार्ड और रोजगारपरक प्रशिक्षण जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।

जिलाधिकारी बंसल ने सभी विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे पूरी तैयारी के साथ शिविर में प्रतिभाग करें। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के आवेदन फॉर्म और उनसे संबंधित पूरी जानकारी के साथ विभाग पहुंचे, ताकि मौके पर ही लोगों को शत-प्रतिशत लाभ मिल सके। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों से 'अंतिम छोर तक के व्यक्ति को योजनाओं से लाभान्वित करने' के उद्देश्य से धरातल पर कार्य करने का आह्वान किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रशासन जनता के द्वार पहुंचकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करे।

शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप, सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए ऐसे बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन देहरादून प्रशासन की महत्वपूर्ण पहल है। यह शिविर दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।

बचपन में कैंसर से जूझने वाली महिला ने दुर्लभ रूप से प्राकृतिक तरीके से दिया स्वस्थ बच्चे को जन्म

देहरादून, इंडिया वार्ता ब्यूरो। यह एक असाधारण कहानी है हौसले और चिकित्सकीय सफलता की, जहाँ 35 वर्षीय महिला, जो मात्र आठ वर्ष की आयु में डिम्बग्रंथि (ओवेरियन) कैंसर को मात दे चुकी थीं, ने मणिपाल अस्पताल, मुकुंदपुर में डॉ. बिस्वज्योति गुहा (कंसल्टेंट प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ) की देखरेख में प्राकृतिक रूप से एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। यह दुर्लभ मामला डॉ. गुहा और मणिपाल अस्पताल का तीसरा ऐसा सफल प्रसव है जिसमें बचपन में ओवेरियन कैंसर से जूझी महिला ने संतान को जन्म दिया है कृ लेकिन पहली बार यह बिना किसी सहायक प्रजनन तकनीक के संभव हुआ है। 35 वर्षीय पौलोमी घोष, जादवपुर निवासी, गर्भावस्था के 30वें सप्ताह में तीव्र ऊपरी पेट दर्द की शिकायत के साथ मणिपाल अस्पताल में भर्ती की गई थीं। प्रारंभिक जांच में परफोरेटेड अपेंडिक्स और अपेंडिकुलर लंप की आशंका जताई गई थी। पहले उन्हें एक अन्य अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें मल्टीस्पेशलिटी सुविधाओं वाले मणिपाल अस्पताल भेजा गया। यहां उन्हें डॉ. संजय मंडल (कंसल्टेंट दृ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी एवं जनरल सर्जन) की देखरेख में प्ट एंटीबायोटिक्स से इलाज मिला। बाद में डत्प् से अपेंडिक्स सामान्य पाया गया, जिससे ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं रही और चिकित्सकीय निगरानी में इलाज किया गया। डॉ. बिस्वज्योति गुहा ने उनकी गर्भावस्था की स्थिति पर बारीकी से निगरानी रखी। उन्होंने कहा, "यह गर्भावस्था कई कारणों से बेहद जटिल थी कृ एक तरफ संभावित सर्जिकल इमरजेंसी, दूसरी ओर उनकी दुर्लभ चिकित्सकीय पृष्ठभूमि और बाद में गंभीर ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस का विकास। उनकी लिवर फंक्शन को दवाइयों से नियंत्रित किया गया। इस मामले को असाधारण बनाने वाला पहलू यह है कि पौलोमी मात्र 8 वर्ष की उम्र में जर्म सेल ट्यूमर के कारण एक ओवरी गंवा चुकी थीं। इसके बाद कीमोथेरेपी भी हुई थी। इसके बावजूद उन्होंने प्राकृतिक रूप से गर्भधारण किया, जो कि बेहद दुर्लभ है। हम यह देखकर खुश हैं कि प्रसव से पहले उनकी स्थिति स्थिर हो गई थी और 38वें सप्ताह में उन्होंने 2.8 किलोग्राम की स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। ऐसे मामलों में प्ट्थ् की आवश्यकता सामान्य है, लेकिन यह एक अपवाद है। मणिपाल अस्पताल में यह तीसरा ऐसा मामला है, लेकिन पहला जिसमें प्राकृतिक गर्भधारण हुआ।

भगवान शंकर आश्रम- मसूरी में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बेसहारा 21 परिवारों को फ्री राशन वितरित

इंडिया वार्ता ब्यूरो

मसूरी (देहरादून) । उत्तराखंड। देवभूमि

उत्तराखण्ड में अवस्थित आर्यम इंटरनेशनल फ़ाउंडेशन के तत्त्वावधान में संचालित भगवान शंकर आश्रम द्वारा घोषित माँ अन्नपूर्णा भंडारा कार्ड योजना के अन्तर्गत स्वाति नक्षत्र की शुभ वेला में वैशाख पूर्णिमा को क्षेत्र के अतिनिर्धन और वंचित 21 परिवारों को मई माह का नि:शुल्क मासिक घरेलू राशन वितरित किया गया।

ट्रस्ट के अध्यक्ष और आश्रम के मुख्य अधिष्ठाता परमप्रज्ञ जगतगुरु प्रोफ़ेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्यम जी महाराज के निर्णय के अनुसार आश्रम द्वारा यह अभियान गत मार्च 2020 से संचालित है।मानव कल्याण, समाज के उत्थान, एवं पुण्यमार्ग हेतु अन्नदान महादान कहलाया है।

श्री गुरुदेव का कथन है कि जो भी आप बाँटते हैं वही आप पाते हैं। आपके कर्म से ही आपका प्रारब्ध सिंचित और भविष्य पल्लवित होता है। आज के दौर में जहाँ चहुं ओर बाज़ारवाद विकसित हो रहा है, और हर कर्म का हेतु पूर्वनियोजित किया जा रहा है , वहीं आर्यम गुरुदेव फ्री राशन बाँट एक नई सहयोग धारा को विकसित कर रहे हैं।

कोरोना काल से चल रही इस योजना ने सैकड़ों परिवारों की मदद एवं उनके जीवन में नई उमंगों का उदय किया है। शुरुआती दौर में प्रतिसाप्ताह सौ से अधिक निर्बल लोगों को राशन बाँटा जाता था। आज भी ज़रूरत के अनुसार लोगों को राशन के साथ दवाइयाँ और अन्य उपयोग में आने वाली वस्तुएँ बाँटी जाती हैं। ट्रस्ट की अधिशासी प्रवक्ता माँ यामिनी श्री ने बताया कि जगद्गुरु प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्यम जी महाराज के सनिध्य में भगवान शंकर आश्रम जन कल्याण हेतु अन्य योजनाएँ भी संचालित करता है। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु "मेरा पौधा, मेरा जीवन, मेरे संग" अभियान 2016 से अद्यतन है। हाल ही में मसूरी वासियों के लिए नि:शुल्क नेत्र परीक्षण शिविर भी आश्रम द्वारा लगाया गया था। जिसमें पचास से अधिक लाभार्थियों को चशमें दिए गए।

श्री गुरुदेव सभी ईश्वर के भक्तों से आह्वान करते हैं कि अपने जीवन में जब अवसर मिले अन्न का दान ज़रूर करें। हिन्दू धर्म में इसी कारण से तुलादान विशेष महत्त्व रखता है। हम अन्न का दान करके स्वयं के आरोग्य को सुरक्षित करते हैं एवं जीवन से संबंधित अन्य अड़चनों को दूर करते हैं। किसी भी प्राणी की क्षुधा को

शांत करने से बड़ा कर्म और कुछ नहीं होता। इसीलिए माँ अन्नपूर्णा के आगे भगवान शिव भी मस्तक टेकते हैं। भंडारा कार्ड धारक व्यक्तियों को दी जाने वाली सामग्री में सभी वस्तुओं की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाता है। इन वस्तुओं में 15 किलो गेहूँ का आटा, 10 किलो चावल, 5 किलो चीनी, दो किलो काला चना, दो लीटर सरसों का तेल, चायपत्ती, धनिया पावडर, लाल मिर्च, हल्दी प्रत्येक 250 ग्राम, एक किलो नमक आदि प्रदान किया जाता है। अति निर्बल, बीमार और आने में असमर्थ परिवारों को राशन उनके घरों पर भी पहुँचाया जाता है। बच्चों द्वारा त्याग दिए गए वृद्ध व्यक्तियों ,निराश्रित विधवाओं, बेसहारों के अपंग, बीमार और अत्यंत निर्धन व्यक्तियों के लिए यह भंडारा कार्ड योजना आश्रम की तरफ़ से संचालित है जिसे शीघ्र ही अन्य अनेक स्थानों तक विस्तारित किया जाएगा। आज के इस वितरण कार्यक्रम में हरीश त्यागी, सोमलता दलाल, अजय त्यागी, प्रीतेश आर्यम, संतोष, सतीश, अरविंद शर्मा, अंजलि सोनकर, रुचि , रीना चौहान , कविता मलिक , रेणु सचदेवा इंदिराबेन मिश्रा आदि का सहयोग रहा।

न्यायपालिका की आलोचना मौजूदा राजनीतिक माहौल

अजीत द्विवेदी

न्यायिक सक्रियता की हमेशा आलोचना होती रही है। यह आम धारणा है कि सरकार कमजोर होती हैं तो न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है और वह विधायिका व कार्यपालिका दोनों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है या करने की कोशिश करती है। भारत में न्यायिक सक्रियता की सबसे तेज गूंज तभी सुनाई दी थी, जब देश में गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू हुआ।

आठवें दशक के आखिरी दिनों से लेकर समूचे नब्बे के दशक में भी न्यायपालिका खूब सक्रिय रही। अनायास नहीं है कि उसी दौर में जजों की नियुक्ति और तबादले का कॉलेजियम सिस्टम भी शुरू हुआ। उस समय सर्वोच्च अदालत के फैसलों से कई नीतियां तय हुईं। आरक्षण की सीमा तय करने से लेकर क्रीमी लेयर बनाने तक के सारे काम उसी दौर में हुए।

तब भी न्यायपालिका की खूब आलोचना होती थी। लेकिन उस समय की आलोचना और अभी हो रही आलोचना में एक बुनियादी फर्क है। उस समय अदालतों के फैसले के गुणदोष पर ज्यादा चर्चा होती थी। हर फैसले को उसके गुणदोष की कसौटी पर कसा जाता था। आलोचना के लिए संवैधानिक तर्क दिए जाते थे। लेकिन अब आलोचना में बौद्धिक दरिद्रता झलकती है। अब फैसले के गुणदोष पर बात नहीं होती है और न फैसले को गलत साबित करने के लिए कोई संवैधानिक तर्क दिया जाता है। अब न्यायपालिका की आलोचना राजनीति में चलने वाले कुतर्कों से की जाती है।

मिसाल के तौर पर तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विधानसभा से पारित 10 विधायकों को लंबे समय तक लंबित रखने के मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो आलोचना हो रही है उसमें इस फैसले को संवैधानिक प्रावधानों की कसौटी पर गलत साबित करने का एक भी तर्क नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अदालतें कानून बनाने लगेंगी तो संसद और विधानसभाओं में ताला लगा देना चाहिए। लेकिन क्या कोई बता सकता है कि अदालत ने कौन सा कानून बना दिया है? कानून तो बना हुआ है कि विधानसभा से पारित किसी भी विधेयक को राज्यपाल मंजूरी देंगे या वापस लौटाएंगे या राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजेंगे।

यही तीन विकल्प हैं। कानून में यह भी लिखा हुआ है कि अगर राज्यपाल ने विधेयक लौटाया है और विधानसभा उसे दोबारा पारित करके भेजेगी तो अनिवार्य रूप से राज्यपाल को उस पर मंजूरी देनी होगी। यह सब संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन इस कानून में एक लूपहोल खोज लिया गया कि इसमें यह नहीं लिखा गया है कि कितने समय में बिल को मंजूरी देनी है या कितने समय में लौटाना है। इस लूपहोल के आधार पर बिल तीन तीन साल लटका दिए गए।

सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या की है और उसकी विसंगति को दूर किया है। सोचें, आमतौर पर कानून से बचने के लिए आरोपियों के वकील कानून के लूपहोल्स निकालते हैं। लेकिन जब संवैधानिक प्राधिकार लूपहोल्स का इस्तेमाल करने लगे तो क्या किया जाए!

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का

विरोध करने वाले तमाम सांसदों, नेताओं, कथित बुद्धिजीवियों, यूट्यूबर्स आदि को पढ़ने और उनके वीडियो सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि मेरिट पर भले फैसला सही हो लेकिन न्यायपालिका में बहुत कमियां हैं इसलिए उनका फैसला गलत है। फैसले का विरोध करने वाले %विद्वानों' ने जो तर्क दिए, उनमें से कई बहुत दिलचस्प हैं।

कहा गया, कॉलेजियम के जरिए जजों की नियुक्ति और तबादले होते हैं और इसमें भाई-भतीजावाद होता है, अमुक व्यक्ति को जमानत देने के लिए एक चीफ जस्टिस ने एक दिन में दो बार बेंच बदली, अमुक व्यक्ति के लिए छुट्टी के दिन बेंच बैठी, अमुक व्यक्ति के मामले में सुनवाई के लिए आधी रात को अदालत खुली, अमुक जज के यहां से नोटों के बंडल निकले लेकिन एफआईआर नहीं हुई, अदालतों में बहुत छुट्टियां होती हैं, अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं, जज महीनों तक फैसला सुरक्षित रख लेते हैं, जज अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देते हैं आदि आदि।

%विद्वानों' ने यह साबित किया है कि अदालतें अब भी कांग्रेस के हिसाब से चलती हैं क्योंकि कांग्रेस आजादी के समय से वकीलों की पार्टी रही है। यह भी कहा जा रहा है कि अमुक वकील के पिता भी किसी हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल थे या अमुक आरोपी के पिता कई बरसों तक अटॉर्नी जनरल रहे। सोचें, इसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति पर दिए गए फैसले का पहलू कहां है? बौद्धिक दरिद्रता का आलम यह है कि न्यायपालिका की आलोचना के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू की सरकार द्वारा किए गए पहले संविधान संशोधन की तरफदारी की जा रही है और यह भी याद दिलाया जा रहा है कि इंदिरा गांधी व राजीव गांधी ने हैसियत बता दी थी न्यायपालिका की।

इस पूरी जमात का सबसे बड़ा बौद्धिक तर्क यह है कि देश के करोड़ों लोगों ने जिनको चुना है वे सबसे ऊपर हैं और काला कोट पहनने वाले दो या पांच लोग तय नहीं करेंगे कि देश के लिए क्या अच्छा है। यह एक धूर्ततापूर्ण तर्क है, जो संवैधानिक व्यवस्था की बजाय चुनी हुई सरकार की तानाशाही की तरफदारी करता है।

अगर इस तर्क को मानें कि चुनी हुई सरकार सबसे ऊपर है और उसे ही यह तय करने का अधिकार है कि देश और उसकी जनता के लिए क्या अच्छा है तो फिर किसी भी मसले पर अदालतों के फैसलों की क्या जरुरत है? सोचें, यही कुपढ़ और अपढ़ लोग जो एक फैसले के लिए न्यायपालिका की बखिया उधेड़ रहे हैं उन्होंने उसी न्यायपालिका के कितने फैसलों का जश्न मनाया है! जब काला कोट पहनने वाले लोग कुछ भी तय नहीं कर सकते हैं तो फिर उनके फैसलों पर जश्न मनाने की क्या जरुरत है? असल में इनकी तारीफों की तरह ही इनकी आलोचना भी दिशाहीन और बुद्धिनिरपेक्ष है।

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की जमीन हिंदू पक्ष को दे दी और कहा कि मुस्लिम पांच किलोमीटर दूर मस्जिद बनाएं तो अदालत की जय जयकार हुई। अदालत ने कह दिया कि ईवीएम से चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं है तो अदालत की जय जयकार हुई। अदालत ने कहा कि पांच से ज्यादा वीवीपैट मशीनों का ईवीएम से मिलान करने की जरुरत नहीं है तो अदालत की जय जयकार हुई। अदालत ने कहा कि वाराणसी के ट्रायल कोर्ट के जज ने ज्ञानवापी के सर्वे की मंजूरी देकर ठीक किया है क्योंकि सर्वे से किसी धर्मस्थल की संरचना नहीं बदल रही है और इसलिए यह धर्मस्थल कानून का उल्लंघन नहीं है तो अदालत की जय जयकार हुई।

अदालत ने कह दिया कि चुनावी बॉन्ड से चंदा अवैध था लेकिन पार्टियों को मिला चंदा वापस लेने या उसकी जांच की जरुरत नहीं है तो अदालत की जय जयकार हुई, अदालत ने तीन तलाक को अवैध घोषित कर दिया तो उसकी जय जयकार हुई, अदालत ने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया तो उसकी जय जयकार हुई। लेकिन उसी अदालत ने कह दिया कि विधानसभा से पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा एक निश्चित समय सीमा में मंजूरी दे दी जानी चाहिए तो फिर अदालत की सारी कमियां और जजों की कई पुश्तों की सच्ची झूठी कहानियां सामने आ जाती हैं।

अदालत वाक व अभिव्यक्ति की आजादी बचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66ए को निरस्त कर दे या फिर समलैंगिकता को अपराध बनाने वाली धारा को निरस्त कर दे तो फिर अदालत की ऐसी तैसी कर दी जाती है।

इन्हीं कुतर्कों के आधार पर अगर विधायिका और कार्यपालिका के बारे में विचार किया जाए तो क्या होगा? लोकसभा के करीब आधे सांसदों के ऊपर आपराधिक मामले हैं। हत्या, बलात्कार, डकैती, बैंक लूट, चोरी, अपहरण, हत्या के प्रयास, मारपीट, बैंक फ्रॉड, ठगी, धोखाधड़ी जैसे आपराधिक मामलों के आरोपी संसद और विधानसभाओं में हैं। सांसदों पर पैसे लेकर वोट देने और पैसे लेकर प्रश्न पूछने के आरोप लगे हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों के झूठे ट्रैवल बिल बनाने का किस्सा भी कुछ समय पहले सामने आया था।

निर्वाचित प्रतिनिधियों पर अपनी निधि का पैसा कमीशन लेकर बेचने की आरोप लगते रहे हैं और कहीं भी इसकी कहानियां सुनने को मिल सकती है। राजनीति में वंशवाद फलफूल रहा है और धनबल, बाहुबल से लोग चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह के सभी लोग कानून बना सकते हैं क्योंकि इनको जनता ने चुना है लेकिन कानून की पढ़ाई करके और बरसों प्रैक्टिस के बाद जज बने लोग कानून की व्याख्या नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे कॉलेजियम से चुने जाते हैं, छुट्टी बहुत करते हैं, मुकदमे बहुत लंबित हैं आदि आदि।

बहरहाल, तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जितना भी बोला या लिखा गया है उसमें कहीं भी यह सुनने या पढ़ने को नहीं मिला कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद का सृजन करते समय संविधान सभा में क्या बहस हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? प्रोफेसर केटी शाह ने क्या कहा और क्या संशोधन प्रस्तावित किया? टीटी कृष्णामचारी ने क्या कहा? इमरजेंसी के समय क्या हुआ था? उससे एक साल पहले शमशेर सिंह बनाम पंजाब सरकार के केस में क्या हुआ था?

अभी हाल के दिनों में नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर के मामले में क्या हुआ था? फर्स्ट या सेकंड जज केस क्या है? गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार या केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार या मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार का केस क्या है? संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत कैसे और किन परिस्थितियों में सामने आया? कॉलेजियम का सिस्टम किन हालात में बना? बस मुंह उठाए और आलोचना कर दी। चूंकि न्यायपालिका की आलोचना मौजूदा राजनीतिक माहौल के अनुरूप है तो अनापशनाप तर्क गढ़ कर आलोचना की जा रही है।

वर्षों बाद भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं

कॉमनवेल्थ घोटाले का मुकदमा भी ढह गया है। कहा जा सकता है कि जांच एजेंसियों और लेट-लतीफ न्याय व्यवस्था की खामी के कारण ऐसा हुआ है। मगर 15 साल बाद भी व्यवस्था नहीं सुधारी, तो उसके लिए दोषी कौन है? कॉमनवेल्थ खेल घोटाले का मुकदमा भी ढह गया है। दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुकदमा बंद करने की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। यह कथित घोटाला उस कथानक का एक बड़ा पहलू था, जिसको लेकर 2010-11 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खड़ा किया गया। 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला, कोयला खदान आवंटन घोटाला और मुंबई की आदर्श हाउजिंग सोसायटी घोटाला इसके अन्य पहलू थे। तत्कालीन यूपीए सरकार ने उन सभी मामलों में कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की। सत्ता पक्ष से जुड़े कई नेताओं को अपने पद छोड़ने पड़े। कुछ को जेल की हवा भी खानी पड़ी। जो नेता जेल गए, उनमें सुरेश कलमाडी भी थे, जो कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण घेरे में आए थे। मगर तत्कालीन सरकार की कार्रवाइयों को अविश्वसनीय बताने का ऐसा जोरदार अभियान छेड़ा गया कि मनमोहन सिंह सरकार और कांग्रेस पार्टी की छवि खलनायक की बन गई। अन्ना आंदोलन और उसके गर्भ से निकली आम आदमी पार्टी उस आंदोलन के मूर्त रूप थे। लेकिन उसके पीछे बड़े सियासी और औद्योगिक हितों के हाथ की चर्चा तब से लेकर आज तक रही है। भारत के इतिहास में जब विवेकहीनता के मौजूदा माहौल की चर्चा होगी, तो इसकी जड़ों की तलाश उसी दौर में की जाएगी। तब भ्रष्टाचारियों को सरेआम फांसी पर लटकाने की मांग को लेकर उभारे गए जन उद्वेग ने आगे चल कर अन्य मसलों पर भी उसी तरह का माहौल बनाने का रास्ता साफ किया। जबकि न्यायिक धरातल पर उन कथित घोटालों से जुड़े एक के बाद एक मुकदमे ढहते चले गए। तब जिन्हें भ्रष्टाचारी मान लिया गया था, उनमें से ज्यादातर अब बरी हो गए हैं। कहा जा सकता है कि यह जांच एजेंसियों और लेट-लतीफ न्याय व्यवस्था की खामी है, जिससे इल्जाम साबित नहीं हो पाए। मगर मुद्दा यह है कि 15 साल बाद भी इस व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ और आरोपी बरी हो गए, तो उसके लिए दोषी कौन है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो आक्रोश और उद्वेग उस समय दिखा, वह आज क्यों गायब हो गया है?

मुख्यमंत्री की 'अमिट प्रेरणा': देहरादून बना बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन का मॉडल

'आयुष्मान भव:' अभियान ने पकड़ी रफ्तार राज्य का पहला आधुनिक इंटेंसिव चाइल्ड सेंटर तैयार, दो साल के लिए बढ़ाया गया धन और आसरा व्यवस्था

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून । देहरादून जिले को बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम से पूरी तरह मुक्त बनाने के संकल्प के साथ जिला प्रशासन ने अपनी महत्वाकांक्षी %आयुष्मान भव:% पहल को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। जिलाधिकारी सविन बंसल की दूरदर्शी सोच और अटूट प्रेरणा से, जिले में न केवल एक सशक्त बाल भिक्षावृत्ति निवारण तंत्र विकसित किया गया है, बल्कि राजधानी में राज्य का पहला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इंटेंसिव चाइल्ड सेंटर भी बनकर तैयार हो गया है, जो अब मासूमों के लिए उम्मीद की नई किरण बन गया है।

कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जिला बाल संरक्षण इकाई की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी बंसल ने बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के लिए धन व्यवस्था, शिक्षकों के समझौते, रेस्क्यू वाहन टीमों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की आसरा व्यवस्था को सीधे दो साल के लिए और अधिक विस्तार देने की घोषणा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारी सिर्फ आधिकारिक ही नहीं, बल्कि कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी हैं प्रशासन की, हर व्यक्ति की, हम सबकी। जिलाधिकारी ने दोहराया कि उनका लक्ष्य जिले को हर हाल में भिक्षावृत्ति और बाल श्रम से मुक्त करना है, जिसके लिए जिला प्रशासन निरंतर अभियान चलाकर बच्चों इनमें 47 बच्चे बाल भिक्षावृत्ति में संलिप्त पाए गए (40 बालक, 7 बालिकाएं), 47 बालक बाल श्रम में, और 72 बच्चे कूड़ा बीनते हुए (62 बालक, 10 बालिकाएं) पाए गए। इसके अतिरिक्त, 8 अन्य बच्चों (4 बालक, 4 बालिकाएं) को भी रेस्क्यू कर इंटेंसिव केयर सेंटर में पंजीकृत किया गया है। केंद्र में 146 बाहरी छात्र (82 बालक, 64 बालिकाएं) भी शामिल हैं।

अभियान में गैर-सरकारी संगठनों जैसे आसरा ट्रस्ट, खुला आश्रय गृह समर्पण सोसाइटी और खुला आश्रय गृह सरफिना ट्रस्ट देहरादून के साथ हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिए कि इन गृहों में आवश्यक सुविधाओं और मानकों को विकसित करने के लिए एक नई आरएफटी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) जारी की जाए, जिसमें प्रशासन पर्यवेक्षक की भूमिका में रहेगा।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद ढौंडियाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, उप श्रम आयुक्त दीपक कुमार, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष नमिता ममगाई, तथा आसरा, समर्पण एवं सरफिना ट्रस्ट के प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे। जिला प्रशासन देहरादून ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिले को हर हाल में बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम मुक्त बनाना ही उनका सर्वोपरि लक्ष्य है। को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। साधु राम इंटर कॉलेज, राजा रोड स्थित यह इंटेंसिव चाइल्ड सेंटर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जहां बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच आरबीएसके की चिकित्सकीय टीम द्वारा प्रत्येक मंगलवार को की जाती है, जिससे उनके शारीरिक विकास और स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी सुनिश्चित होती है। इस केंद्र से अब तक 19 बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ते हुए विभिन्न स्कूलों में दाखिला दिलाया गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि भिक्षावृत्ति, बाल श्रम से रेस्क्यू बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना ही प्रशासन का लक्ष्य है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि %बाल भिक्षावृत्ति निवारण प्रयास% अभियान के अंतर्गत माह दिसंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक कुल 174 बच्चों को बाल भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और कूड़ा-बीनने जैसे कार्यों से रेस्क्यू किया गया है।

मई के आखिर में जारी हो सकती है त्रिस्तरीय पंचायत अधिसूचना

ओबीसी आरक्षण व पंचायतीराज एक्ट संशोधन पर फंसा हुआ है पेंच

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून । उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर फिलहाल सरकार असमंजस की स्थिति में है। एक तरफ पंचायतीराज एक्ट का संशोधन नहीं हो पाया है, तो दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण का भी निर्धारण सरकार नहीं कर पाई है। हालांकि, इस सबके बावजूद सरकार की निगाह राजभवन पर है। जहां पंचायतीराज एक्ट में संशोधन अध्यादेश लटका हुआ है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि राजभवन से अध्यादेश को हरी झंडी मिलते ही इसी माह के अंत तक अधिसूचना जारी हो सकती है।

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतें फिलहाल प्रशासकों के भरोसे चल रही हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी हुई हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल नवंबर, दिसंबर महीने में ही पूरा हो चुका था। ऐसे चुनाव प्रक्रिया पूरी न होने के कारण सरकार के लिए पंचायतो में प्रशंसकों को बैठना मजबूरी बन गया था। उत्तराखंड के 13 जिलों में से हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी 12 जिलों में पंचायत के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं, जबकि हरिद्वार में पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव के साथ ही होते हैं। प्रदेश के 12 जिलों में पंचायतों का कार्यकाल 28 नवंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को खत्म हो गया था, लेकिन इसके बावजूद सरकार विभिन्न औपचारिकताएं पूरी न करवा पाने के कारण चुनाव नहीं करवा पाई।

एक्ट के अनुसार प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने का ही हो सकता है। दिया गया यह समय इसी महीने पूरा हो रहा है। जाहिर है सरकार को कार्यकाल पूरा होने से पहले निर्णय लेना है, लेकिन, यदि सरकार को चुनाव कराने हैं तो उसे संशोधित पंचायती राज एक्ट लागू करवाना होगा। इसके बाद ओबीसी आरक्षण भी तय करना होगा। सरकार की यह तैयारी पूरी होने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर पाएगा। हालांकि, राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त सुशील कुमार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से आयोग के तैयार होने की बात कहते दिखाई देते हैं। ऐसे में गेंद सरकार के पाले में है कि सरकार कब तक चुनाव को लेकर जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करवा पाती है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जा चुका है। अब ओबीसी आरक्षण का निर्धारण होना ही बाकी रह गया है। तकनीकी रूप से पेंच पंचायती राज एक्ट के संशोधन पर फंसा है। जिसके बाद ही आरक्षण के निर्धारण पर फैसला हो पाएगा। उधर संशोधन से जुड़ा अध्यादेश फिलहाल राजभवन में विचाराधीन है।

देहरादून में चमके अल्मोड़ा के कराटे खिलाड़ी, झटके 15 पदक

अल्मोड़ा (इंडिया वार्ता ब्यूरो)। देहरादून में 9 से 11 मई तक आयोजित 22वीं उत्तराखंड राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में अल्मोड़ा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 15 पदक अपने नाम किए। इनमें तीन स्वर्ण, तीन रजत और नौ कांस्य पदक शामिल हैं। प्रतियोगिता सब-जूनियर, कैडेट, जूनियर और सीनियर वर्ग के बालक-बालिकाओं के लिए आयोजित की गई थी। कराटे एसोसिएशन अल्मोड़ा के महासचिव एवं कोच हरीश सिंह चौहान ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ियों ने आत्मविश्वास और तकनीकी कौशल के साथ शानदार खेल दिखाया। विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखंड कराटे एसोसिएशन के महासचिव संजीव कुमार जांगड़ा, जिला क्रीड़ा अधिकारी देहरादून, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के प्रधानाचार्य मंगेश ममगाई, अंतरराष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी लक्ष्मण सिंह, तथा खेल विभाग के कोच दीपक अधिकारी और दीपक कुमार द्वारा पदक और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में चंदन भट्ट, विनोद जोशी और कुसुम लता ने स्वर्ण पदक हासिल किया। रजत पदक जीतने वालों में पार्थिक गुर्रानी, तनुजा जीना और लीलावती का नाम शामिल है। वहीं कांस्य पदक विजेता दीपक भट्ट, पूजा बिष्ट, ज्योति बिष्ट, प्रवजल धानिक, सिद्धार्थ धानिक, प्रेम सिंह गैड़ा, नीरज भैंसवड़ा, अंजली बिष्ट और सोनू कुमार रहे। कोच चौहान ने बताया कि स्वर्ण पदक विजेताओं का चयन जून में होने वाली सब-जूनियर व जूनियर नेशनल कराटे प्रतियोगिता के लिए किया गया है, जबकि अन्य पदक विजेता दिल्ली में आयोजित होने वाली ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में भाग लेंगे। इस उपलब्धि पर जिला क्रीड़ा अधिकारी महेश्वरी आर्या, उप क्रीड़ा अधिकारी अरुण बंग्याल, जिला युवा कल्याण अधिकारी सोनू कुमार, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी अशोक कुमार, ब्लॉक खेल समन्वयक राजेंद्र सिंह नयाल तथा क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं और खेल प्रेमियों ने विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

केनरा रोबेको ने लॉन्च किया केनरा रोबेको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड

देहरादून, इंडिया वार्ता ब्यूरो। भारत के दूसरे सबसे पुराने एसेट मैनेजर, केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड ने आज केनरा रोबेको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के लॉन्च का ऐलान किया है। यह एक ओपन-एंडेड हाइब्रिड फंड है जिसका लक्ष्य बाजार के अच्छे प्रदर्शन के समय अल्फा रिटर्न हासिल करना और बाजार के खराब दौर में नुकसान की संभावना को कम करना है। यह फंड एक ओपन-एंडेड स्कीम है जो इक्विटी और इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट, डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में निवेश करती है। इसकी मल्टी असेट एलोकेशन रणनीति का लक्ष्य सभी तरह की बाजार स्थितियों में बेहतर परिणाम हासिल करना है। यह फंड बदलती आर्थिक स्थितियों, अर्निंग मोमेंटम, मार्केट वैल्यूएशन और इक्विटी रिस्क प्रीमियमको ध्यान में रखते हुए समय-समय पर असेट क्लॉस की समीक्षा करता रहेगा जिससे पोर्टफोलियो को संतुलित रखने में आसानी होगी। नया फंड ऑफर सब्सक्रिप्शन के लिए 9 मई, 2025 को खुलेगा और 23 मई, 2025 को बंद होगा। केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफीसर, रजनीश नरूला ने कहा, केनरा रोबेको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के लॉन्च से न केवल हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार होगा, बल्कि यह निवेशकों को बाजार की नई-नई जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग-अलग तरह के समाधान प्रदान करने की हमारी क्षमता को भी बढ़ाएगा। हमारा लक्ष्य निवेशकों के लिए लगातार नए फंड विकसित करना और उन्हें मजबूत पोर्टफोलियो बनाने में सहायता करना है। हम निवेशकों के वित्तीय लक्ष्यों के मुताबिक प्रोडक्ट विकसित करने के साथ ही इनमें लगातार सुधार करते रहते हैं और उत्कृष्टता की अपनी संस्कृति पर फोकस बनाए रखते हैं।

रेड 2 की सफलता से वाणी कपूर बेहद खुश, बोलीं-ये सब सपने के सच होने जैसा

2018 की हिट फिल्म रेड का सीक्वल रेड 2 सिनेमाघरों में धमाल मचा रहा है। इसका जलवा बॉक्स ऑफिस पर साफ देखा जा सकता है। रविवार को फिल्म ने 70.50 करोड़ रुपये कमाए, जिससे यह 100 करोड़ क्लब की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। फिल्म की कमाई से स्टार कास्ट काफी खुश है। वाणी कपूर भी! जिन्होंने मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाया है।

वाणी कपूर काफी खुश हैं कि उनकी फिल्म रेड 2 सिर्फ चार दिनों में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई है।

अभिनेत्री ने फिल्म की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा, बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाना खास अहसास होता है, जैसे कोई सपना सच हो रहा हो। जब आप ऐसी फिल्म का हिस्सा बनते हैं जो दर्शकों से जुड़ती है, तो यह देखकर काफी अच्छा लगता है। फिल्म को मिल रही प्रतिक्रिया दिल को छू लेने वाली है। मैं इस फिल्म का हिस्सा बनकर खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस कर रही हूं। वाणी फिल्म में अपनी एक्टिंग के लिए चारों ओर से तारीफें बटोर रही हैं। उन्होंने कहा, इस फिल्म की कहानी बहुत दमदार है। निर्देशक राज कुमार गुप्ता के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करना मेरे लिए शानदार अनुभव रहा है। इस फिल्म से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरे किरदार की सराहना के लिए आप सभी का धन्यवाद।

रेड टू की अभिनेत्री ने आगे कहा, अजय देवगन सर और राज कुमार गुप्ता सर के साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा, जिससे मैं एक कलाकार के तौर पर और बेहतर बन पाई हूं। फिल्म की सफलता मेरे लिए बहुत मायने रखती है। दर्शकों से मिलने वाली प्रतिक्रिया मुझे मेहनत करने और लगातार बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है।

फिल्म रेड 2 में अजय देवगन और वाणी कपूर के अलावा अमित सियाल, रितेश देशमुख, यशपाल शर्मा, सौरभ शुक्ला और सुप्रिया पाठक लीड रोल में हैं।

एनएसडीसी इंटरनेशनल केयरगिवर्स को प्रशिक्षण प्रदान कर दे रहा विश्वस्तरीय अवसर

देहरादून, इंडिया वार्ता ब्यूरो। एनएसडीसी इंटरनेशनल दुनिया भर में केयरगिविंग सेगमेन्ट में कौशल की खामियों को दूर करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है, एनएसडीसी इंटरनेशनल ने ग्लोबल हेल्थकेयर की क्षमता बढ़ाने के लिए तकरीबन 1 लाख केयरगिवर्स को प्रशिक्षित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। गौरतलब है कि दुनिया भर में इन प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। अब तक संगठन हज़ारों कुशल केयरगिवर्स को जर्मनी, जापान, यूके और इज़रायल जैसे देशों में नौकरियों के अवसर उपलब्ध करा चुका है। इस प्रशिक्षण के तहत उम्मीदवारों को विशेष सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण तथा अंग्रेज़ी, जर्मन एवं जापानी भाषाओं में कौशल प्रदान किया गया है। ताकि उनकी रोज़गार क्षमता बढ़े और वे दुनिया के विभिन्न कोनों में अस्पतालों एवं चिकित्सा संस्थानों में नौकरी पाकर अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें।

हाल ही में कुछ प्रमुख जापानी एवं जर्मन कंपनियों ने एनएसडीसी इंटरनेशनल (एनएसडीसी की पूर्ण स्वामित्व की सब्सिडरी) के उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन के साथ नौकरी दी थी, जो संगठन द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता को दर्शाता है। आलोक कुमार, सीईओ, एनएसडीसी इंटरनेशनल ने कहा, आज पूरी दुनिया एसडीजी-3 के अनुरूप स्वास्थ्य एवं कल्याण के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में प्रयासरत है। इसी के मद्देनज़र एनएसडीसी इंटरनेशनल में हम हर संभव कोशिश कर रहे है। हम न सिर्फ अनुकूल प्रोग्राम लेकर आए हैं बल्कि उम्मीदवारों को उद्योग जगत की आवश्यकतानुसार कौशल प्रदान करने के लिए देशी-विदेशी संस्थानों के साथ साझेदारी भी की है। ताकि हम हेल्थकेयर की चुनौतियों को दूर करने में योगदान दे सकें। हमने दुनिया भर में हज़ारों कुशल केयरगिवर्स को नौकरी हासिल करने में मदद की है। अपने प्रयासों के द्वारा हम हेल्थकेयर सिस्टम में कुशल प्रोफेशनल्स को शामिल करने के लिए निरंतर अग्रसर हैं।'

हेल्थकेयर सेगमेन्ट की बात करें तो कई देश प्रोफेशनल्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जूझ रहे हैं। संगठन विभिन्न देशों की मांग को पूरा करने के लिए अब तक कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सिंगापुर, जापान और गल्फ कोऑपरेशन काउन्सिल (जीसीसी) देशों के साथ साझेदारी कर चुका है।

एनएसडीसी इंटरनेशनल ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे युनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज बॉक्सहिल लैंग्वेज असेसमेन्ट ट्रस्ट और अग्रणी जापानी एवं जर्मन भाषा प्रदाताओं के साथ भी साझेदारियां की हैं। संगठन ने इज़रायल के लिए भी उम्मीदवारों को हेल्थकेयर में कौशल प्रदान करना शुरू किया है, जहां लगभग 5000 केयरगिवर्स की आवश्यकता है। इसके अलावा उम्मीदवारों को कौशल प्रदान करने और उन्हें विदेशों में अवसर उपलब्ध कराने के लिए जानी-मानी युनिवर्सिटियों एवं स्वदेशी संस्थानों के साथ साझेदारियां भी की हैं। उम्मीदवारों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने तथा प्रतिभाशाली उम्मीदवारों की मांग को पूरा करने के लिए एनएसडीसी इंटरनेशनल ने देश भर में सेंटर स्थापित किए हैं, जहां उम्मीदवारों को ग्लोबल रोल्स के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इन सेंटरों में उम्मीदवारों को सीखने के लिए अनुकूल माहौल और सभी ज़रूरी सुविधाएं मिलती हैं। कुशल प्रशिक्षक उन्हें प्रशिक्षित कर विश्वस्तरीय अवसरों के लिए तैयार करते हैं। एनएसडीसी इंटरनेशनल के कार्य दुनिया भर में हेल्थकेयर सिस्टम में सुधार लाने और लोगों के कल्याण में योगदान दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संगठन भारत को प्रतिभा के विश्वस्तरीय हब के रूप में स्थापित करने के मिशन में योगदान दे रहा है।

फिर पार्टी कार्यालय को लेकर बवाल, कांग्रेसियों की पुलिस से झड़प

नैनीताल, । जिले के रामनगर में रानीखेत रोड पर स्थित कांग्रेस कार्यालय में ताला लगाने को लेकर फिर बवाल हुआ है। कार्यालय में दूसरे पक्ष की ओर से ताला लगाए जाने की सूचना पर कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। जहां उन्होंने अपने पुराने ताले वापस लगवाए। इसी बीच भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर पहुंच गया। जिस पर रणजीत रावत और समर्थकों की पुलिस से झड़प हो गई। पूर्व विधायक ने इस मामले में पुलिस प्रशासन पर सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि सुबह उन्हें सूचना मिली थी कि कांग्रेस कार्यालय के गेट पर लगे उनके ताले को तोड़कर किसी अन्य व्यक्ति ने नए ताले लगा दिए हैं। इस सूचना पर वो मौके पर पहुंचे और अपने पुराने ताले वापस लगवाए, लेकिन इसके तुरंत बाद भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंच गया। पूर्व विधायक रावत ने दावा किया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कहा कि कार्यालय के अंदर कुछ लोग बंद हैं, इस पर कांग्रेस नेताओं ने जवाब दिया कि यह कार्यालय उनका है और अंदर कोई भी उनका व्यक्ति मौजूद नहीं है। इसके बावजूद पुलिस ने ताला तोड़ दिया, जिसकी पुष्टि खुद रणजीत रावत ने मीडिया के सामने की।

रणजीत रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि सबकी मौजूदगी में पुलिस ने ताला तोड़ा है, जो इस बात का प्रमाण है कि पुलिस प्रशासन इस कार्यालय पर कब्जा कराने में शामिल है। यहां तक कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी कह रहे हैं कि ऊपर बात कर लीजिए। इसका मतलब साफ है कि इस कार्रवाई के पीछे ऊपर तक की मिलीभगत है। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं और कुछ को कोतवाली में बैठाया गया है। उन्होंने दो टूक कहा कि वे डरने वाले नहीं हैं, पुलिस की सत्ता के दवाब का विरोध करते रहेंगे.

देहरादून में भू-माफियाओं पर SSP दून का शिकंजा, गैंग लीडर सहित 3 गिरफ्तार

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून । देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के निर्देश पर भू-माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत आज बड़ी कार्रवाई की गई है। लंबे समय से भूमि धोखाधड़ी के मामलों में लिप्त एक गिरोह के सरगना नीरज शर्मा सहित तीन अभियुक्तों को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर पुलिस द्वारा की गई इस त्वरित कार्रवाई से देहरादून में भूमि संबंधी अपराधों को अंजाम देने वालों में हड़कंप मच गया है।

SSP देहरादून ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय भू-माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने और ऐसे अपराधियों पर गुंडा व गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में, रायपुर पुलिस ने नीरज शर्मा पुत्र महेश चंद शर्मा, उसकी पत्नी श्रीमती आशु शर्मा, और कु. ज्योति पंवार पुत्री सोहन सिंह पंवार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट (मु0अ0सं0 - 144/25 धारा - 2/3 गैंगस्टर एक्ट) के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। यह गिरोह जनपद के विभिन्न थानों में भूमि धोखाधड़ी के कई मामलों में वांछित था। एक अन्य अभियुक्त श्रीमती अंजली शर्मा पत्नी दिनेश चंद निवासी काशीपुर, उधमसिंह नगर के विरुद्ध भी गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही की गई है।

SSP के त्वरित गिरफ्तारी के निर्देशों के अनुपालन में, थानाध्यक्ष रायपुर के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। इस टीम ने मुखबिर से मिली सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए आज, 12 मई 2025 को, गैंग लीडर नीरज शर्मा और उसके दो प्रमुख साथियों, श्रीमती आशु शर्मा तथा कु. ज्योति पंवार को रायपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान-

नीरज शर्मा पुत्र महेश चंद शर्मा (गैंग लीडर), निवासी सी-2 कासा टैरेजा अपार्टमेंट, कैनाल रोड देहरादून, हाल पता 1 गोपाल विहार डांडा लखौंड, सहस्त्रधारा रोड, रायपुर, देहरादून।

श्रीमती आशु शर्मा पत्नी नीरज शर्मा (गैंग सदस्य), निवासी सी-2 कासा टैरेजा अपार्टमेंट, कैनाल रोड देहरादून, हाल पता 1 गोपाल बिहार, डांडा लखौंड, सहस्त्रधारा रोड, रायपुर, देहरादून।

कु. ज्योति पंवार पुत्री सोहन सिंह पंवार (गैंग सदस्य), निवासी लेन न0 -2 शिवगंगा एनक्लेव डांडा लखौंड थाना रायपुर, देहरादून।

अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक रिकॉर्ड बेहद लंबा है, जिसमें भूमि धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकी देने जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं

नीरज शर्मा के खिलाफ थाना रायपुर, प्रेमनगर और कैंट में 7 विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र, धमकी और गाली-गलौज के आरोप शामिल हैं।

आशु शर्मा पर थाना रायपुर में धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित 5 मुकदमे दर्ज हैं।

ज्योति पंवार के खिलाफ थाना प्रेमनगर, कैंट और रायपुर में 3 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और धमकी के आरोप हैं।

पुलिस टीम

इस सफल कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक संजय रावत (चौकी प्रभारी बालावाला), महिला उपनिरीक्षक रजनी चमोली, कांस्टेबल सुनील कुमार, कांस्टेबल कृष्णा परिहार और महिला कांस्टेबल अंजू शामिल थीं।

SSP देहरादून ने दोहराया है कि जनपद में भू-माफियाओं के विरुद्ध यह अभियान जारी रहेगा और ऐसे अपराधों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई से देहरादून में भूमि संबंधी धोखाधड़ी पर अंकुश लगने की उम्मीद है।

प्रथम पृष्ठ का शेष मुख्यमंत्री ने डोल आश्रम में श्री ...

है, इसके लिए सरकार कठोर धमार्न्तरण का कानून लेकर आयी है। उन्होंने कहा हमने लैंड जिहाद , लव जिहाद जैसी अनेक साज़िशों पर कार्रवाई करते हुए अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। साथ ही समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश पहला प्रदेश बनने का गौरव उत्तराखंड ने हासिल किया है। सख्त नक़ल विरोधी क़ानून ने प्रदेश के युवाओं को एक निष्पक्ष अवसर प्रदान किया है और प्रत्येक जिले के अभ्यर्थी अब चयन सूची में जगह बना रहे हैं ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डोल आश्रम को पूज्य महाराज कल्याणदास जी ने स्थापित किया। उनकी सोच के अनुरूप यह आश्रम धर्म, आध्यात्म, संस्कृति और शिक्षा क बड़े केन्द्र के रूप में आगे बढ़ रहा है एवं विकसित हो रहा है। उन्होंने महाराज जी का अभिनन्दन करते हुए कहा कि उन्होंने सम्पूर्ण जीवन यहाँ के लोगों की सेवा एवं परमार्थ के कार्यों में लगाया। मुख्यमंत्री ने सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देते हुए महात्मा बुद्ध के धर्म, शान्ति एवं अंहिसा के मार्ग पर चलने का भी आग्रह किया।

इस अवसर पर पूज्य महाराज कल्याणदास ने सभी उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमें अपनी जन्मभूमि के लिए बेहतर कार्य करने होंगे। उन्होंने कहा कि हमें बुरे व्यसनों को त्याग कर आध्यात्म को अपनाना होगा तभी हमारा जीवन एवं समाज सुख समृद्वि प्राप्त कर पायेगा। उन्होंने संस्कृत भाषा को अपनाने पर ज़ोर देते हुए कहा कि जब तक संस्कृत हमारे हृदय में जीवित है , तब तक भारतीयता को कोई खतरा नहीं हो सकता ।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग श्री अजय टम्टा , विधायक जागेश्वर श्री मोहन सिंह मेहरा, अल्मोड़ा विधायक श्री मनोज तिवारी , पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल भाजपा जिलाध्यक्ष श्री महेश नयाल, जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार पांडेय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र पिंचा, मुख्य विकास अधिकारी श्री दिवेश शासनी एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

स्नेहा राणा ने कोलंबो में रचा इतिहास

देहरादून(इंडिया वार्ता ब्यूरो)। प्रतिभाशाली क्रिकेटर व ग्राफिक एरा की छात्रा स्नेह राणा ने कोलम्बों में एक नया इतिहास रच दिया है। वे महिला वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेकर स्नेह राणा यह रिकॉर्ड बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी की एमबीए की छात्रा व स्पिनर ऑलराउंडर क्रिकेटर स्नेह राणा ने यह इतिहास श्रीलंका में महिलाओं की वन- डे ट्राई नेशन क्रिकेट सीरीज में बनाया है। एक सीरीज में 15 विकेट लेकर स्नेह राणा वर्ष 2003 में ऑस्ट्रेलिया की कैथ्रीन फिट्जपैट्रिक के बनाए वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करने में सफल हो गईं हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैथ्रीन फिट्जपैट्रिक ने 2003 में वर्ल्ड सीरीज के दौरान 15 विकेट लिये थे। स्नेह ने अपनी शानदार गेंदबाजी से यह रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। उन्होंने टूर्नामेंट में श्रीलंका व साउथ अफ्रीका के खिलाफ पंद्रह विकेट लिए। टूर्नामेंट में भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारत की पहली और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कैथरीन फिट्जपैट्रिक के साथ संयुक्त रूप से दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गयी हैं। उन्होंने महिलाओं की श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट लेने का लंबे समय से चला आ रहा भारतीय क्रिकेटर नूशिन अल खादीर का बारह विकेट का रिकार्ड भी तोड़ दिया। ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉ. कमल घनशाला ने स्नेह की इस शानदार उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि स्नेह राणा पर पूरे देश को गर्व है। उत्तराखंड की इस बेटी ने सीरीज में पंद्रह विकेट लेने का इतिहास रचकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्राफिक एरा के साथ ही देश और उत्तराखंड का भी मान बढ़ाया है।

प्रथम पृष्ठ का शेष लाटू में आयोजित कार्यक्रम सिर्फ धार्मिक ..

सरकार पौराणिक मंदिरो का जीर्णोद्धार, सांस्कृतिक धरोहरों कि पहचान कर सरंक्षण करने के साथ ही मंदिरों के आस-पास सुविधाओं का विकास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा वर्तमान में चारधाम यात्रा का संचालन किया जा रहा है। जो देश-दुनिया के सनातन मतावलम्बियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जिसके लिए हमारी सरकार आल वेदर रोड, चिकित्सा सुविधा, आपात समय में हेली सेवा उपलब्ध करवा रही है। जिससे चार धाम यात्रा पर आने वाले किसी भी तीर्थयात्री को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य के विकास के लिए जहां ऑल वेदर रोड़ का निर्माण किया गया है। वहीं ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का भी तेजी से निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही धामों में यात्री सुविधा जुटाने के लिए बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार जनहित के लिए कड़े निर्णय ले रही है। कहा कि हमने राज्य की जनता से समान नागरिक सहिंता लागू करने का वादा किया था। जिसे सरकार ने निभाया है। इसके साथ ही राज्य में धर्मान्तरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून और सख्त भू-कानून लाकर भू माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम किया है।

इस दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां लाटू धाम के विकास के लिए योजना बनाकर कार्य करने का आश्वासन दिया। वहीं कुलसारी में उप जिला चिकित्सालय के निर्माण, बाढ़ सुरक्षा कार्य और हेलीपेड निर्माण को लेकर कार्य करने की बात कही। साथ ही उन्होंने स्थानीय जनता को विधायक की सभी मांगों को दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्प समयावधि की योजनाओं में शामिल करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने आगामी 2026 में आयोजित होने वाली माँ नंदा देवी राजजात यात्रा के लिए सड़कों के साथ ही पार्किंग और यात्री सुविधाओं के विकास करने के लिए योजनाबद्ध कार्य करने की भी बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को मां नंदा देवी राजजात यात्रा के आयोजन को लेकर किए जाने वाले कार्यों को योजनाबद्ध और समयबद्ध तरीके से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजजात यात्रा के कार्यों को लेकर सभी स्तरों पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी के सहयोग से आगामी 2026 में आयोजित होने वाली राजजात यात्रा को भव्य और दिव्य स्वरुप आयोजित किया जाएगा।

इस मौके पर थराली विधायक भूपाल राम टम्टा, कर्णप्रयाग विधायक अनिल, जड़ी-बूटी सलाहाकार समिति के उपध्यक्ष बलबीर घुनियाल, भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल बर्त्वाल आयोजन समिति के अध्यक्ष कृष्णा सिंह, ब्लॉक प्रशासक दर्शन दानू, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कृष्णा सिंह, जिलाधिकारी संदीप तिवारी, पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक संदीप शर्मा ने इंडिया प्रिन्टर शांप न. 06 संगम प्लाजा धर्मपुर देहरादून से मुद्रित करवाकर मोहक्कमपुर खुर्द पोस्ट आई.आई.पी. रेलवे क्रसिंग हरिद्वार रोड़ देहरादून (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया।

प्रधान सम्पादक : संजीव शर्मा

संपादकः संदीप शर्मा

सह सम्पादक : डा. विष्णु बिश्वास

संजीव अग्निहोत्री गढ़वाल प्रभारी

अल्मोड़ा जिला प्रभारी : रोहित कार्की

अल्मोड़ा संवाददाता : रक्षित कार्की

ब्यूरो चीफ : राजीव अग्रवाल

Email.
indiawarta@gmail.com
indiawarta@rediffmail.com
Web Site
www.indiawarta.com
R.N.I NO. UTTHIN/2011/39104
M- 7500471414,7500581414

नोट& समाचार पत्र में सभी पद अवैतानिक हैं। किसी भी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा।

R.N.I NO. UTTHIN/2011/39104

गढ़वाल के पांच दिवसीय दौरे पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत

चमोली में परखेंगे यात्रा व्यवस्थाएं, जिला प्रशासन की लेंगे बैठक
भ्रमण के दौरान श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में योजनाओं का करेंगे लोकार्पण

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून। सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत गढ़वाल मंडल के चार दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह अपनी विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विभिन्न क्षेत्रों में विकास योजनाओं का जायजा लेंगे, साथ ही विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। इसके उपरांत डॉ. रावत चमोली जनपद का भ्रमण करेंगे, जहां वह चार धाम यात्रा से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को परखेंगे। चमोली जिला मुख्यालय में कैबिनेट मंत्री स्थानीय प्रशासन की बैठक लेंगे, इसके साथ ही वह स्वास्थ्य, शिक्षा और सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी विभागीय अधिकारियों से लेंगे।

कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि वह आगामी 17 मई तक गढ़वाल मंडल के दौरे पर रहेंगे। पांच दिवसीय दौरे की शुरूआत वह अपने विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर से करेंगे। जहां वह मंगलवार को सिमखेत में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कर बाढ़ सुरक्षा कार्यों का शिलान्यास करेंगे। बुधवार को डॉ. रावत कलगड़ी मल्ली में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके उपरांत वह कालौं, चमगांव और पटोटी में आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान वह राजकीय इंटर कॉलेज कालौं के नव निर्मित भवन

तथा पटोटी के बहुउद्देशीय पंचायत भवन का लोकार्पण करेंगे साथ ही वह प्राथमिक विद्यालय कालौं व चमगांव के स्वीकृत भवन व सौन्दर्यीकरण का शिलान्यास करेंगे।

गुरूवार को कैबिनेट मंत्री डॉ. रावत भुवनेश्वरी में ब्रिगेडियर विद्याधर जुयाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कर नव प्रवेशित छात्रों के मंगल स्नान एवं यज्ञोपवीत संस्कार में हिस्सा लेंगे और उन्हें दीक्षारम्भ की शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। इसके उपरांत वह ग्वाडीगाड, सरणा, चोपड्यूं और पाबौं में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। जिसमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय ग्वाड़ीगाड, जूनियर हाईस्कूल सरणा के नव निर्मित भवन तथा चोपड्यूं में पंचायत भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद पाबौं में ब्लॉक सभागार एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के इंटरलॉकिंग टाइल रास्ते का लोकार्पण करेंगे। पाबौं में डॉ. रावत व्यापार मंडल के पादधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे।

16 व 17 मई को कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत चमोली जनपद के दौरे पर रहेंगे। जहां वह चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इस दौरान वह यात्रा मार्गों पर स्थित स्वास्थ्य विभाग की स्थाई व अस्थाई चिकित्सा इकाईयों का भी निरीक्षण करेंगे। इसके उपरांत वह जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग के साथ स्थानीय प्रशासन की बैठक लेंगे। जिसमें विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे साथ ही चार धाम यात्रा व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे।

प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपनी जन्मभूमि के प्रति निष्ठावान रहें व उसके विकास में सक्रिय योगदान दे : बंशीधर तिवारी

देहरादून, इंडिया वार्ता ब्यूरो। सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग के महानिदेशक एवं एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपनी जन्मभूमि के प्रति निष्ठावान रहते हुए उसके विकास में सक्रिय योगदान दे। उन्होंने कहा कि भले ही सकारात्मक पलायन हो रहा हो, फिर भी व्यक्ति को अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। बंशीधर तिवारी उत्तरजन टुडे सेंचुरियन क्लब द्वारा आयोजित ष्पहाड़ कैसे हों आबाद? विषयक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार पलायन को रोकने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सीमांत गांवों को पुनः बसाने के प्रयास हो रहे हैं। विगत तीन वर्षों में अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है जिससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार का उद्देश्य पलायन रोकने के साथ-साथ पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। महिला सशक्तीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। सरकार सामाजिक सहभागिता को भी इस दिशा में महत्वपूर्ण मानती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में सरकार संकल्पित है। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त तथा ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि राज्य सरकार मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है। पूरे प्रदेश में मिलावटी उत्पादों की जांच हेतु छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। इसके लिए उपभोक्ताओं को जागरूक भी किया जा रहा है।

ऋषिकेश के नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि पलायन रोकने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग शहरों में बस गए हैं, वे अपने मूल गांवों की ओर भी ध्यान दें। उन्होंने भूमि बंदोबस्त एवं भूमि क्रय-विक्रय को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर मॉडल को उत्तराखंड में अपनाने का सुझाव दिया। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह नेगी ने कहा कि भारत ने हालिया आतंकी घटनाओं के बाद कड़े कदम उठाए हैं और यह दर्शाया है कि देश सामरिक दृष्टि से आत्मनिर्भर है। उन्होंने सिंधु घाटी की नदियों के जल के सदुपयोग के लिए नई रणनीति की आवश्यकता पर बल दिया।

राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने एक सशक्त और प्रतिनिधि पत्रिका की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रकाशन की चुनौतियों और जमीनी कठिनाइयों को विस्तार से बताया। उन्होंने आरटीआई को जनहित का सशक्त माध्यम बताते हुए इसके प्रभावशाली उपयोग पर जोर दिया। कार्यक्रम में उत्तरजन टुडे के संपादक पी.सी. थपलियाल ने पत्रिका के नौ वर्षों की यात्रा को साझा करते हुए कहा कि पत्रिका सीमांत गांवों को बसाने की दिशा में सरकार के प्रयासों में भागीदार बनेगी। अध्यक्षीय संबोधन में शिक्षाविद् एवं पूर्व कुलपति डॉ. सुधा रानी ने पत्रिका की सराहना की और इसे जनता और सरकार के बीच सेतु बताया। संचालन वरिष्ठ पत्रकार वर्षा सिंह ने किया।

उत्तरजन टुडे सम्मान से सम्मानित विभूतियों में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार कर्नल (सेनि) राकेश कुकरेती एवं हवलदार बंशीधर इस्टवाल (1971 युद्ध नायक) शिक्षा क्षेत्ररू नमिता ममगाई (प्रिंसिपल, ओएनजीसी महिला पॉलिटेक्निक), नीरिजा जुयाल डंडरियाल (प्रिंसिपल, सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल), खेलरू संतोष राय (महिला मास्टर्स), निर्मला नेगी (बैडमिंटन), चिकित्सारू डॉ. उदय बलूनी, डॉ. प्रीति पांडे, डॉ. रचित गर्ग, डॉ. मारिषा पंवार, पत्रकारितारू सुरेंद्र डसीला, उद्यमितारू सुशील कुमार (गैस इंजीनियरिंग) संसाधन विकास संजय भार्गव (रीजनल चीफ, हुडको), जनसंपर्कः सुनील राणा, गढ़भोज प्रोत्साहनः द्वारिका प्रसाद सेमवाल, डिजिटल क्षेत्र आकाश शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ब्रिगेडियर बिनोद पसबोला, कर्नल (सेनि) राकेश कुकरेती, कर्नल (सेनि) यदुवीर सिंह रावत, ले. कर्नल उमेश रावत, विपिन बलूनी (एमडी, बलूनी ग्रुप), निशांत थपलियाल (चेयरमैन, आईटीएम), ललित जोशी सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे।

पाठको के लिए

मान्यवर पाठकगण

१. दैनिक इंडिया वार्ता समाचार पत्र हेतु अपने व्यक्तिगत या संस्थान की ओर से प्रकाशनार्थ लेख/समस्याएं व समाचार हमें भेजे व प्रति दिन नियमित रूप से समाचार पत्र प्राप्त करने को कार्यालय से सम्पर्क करे।

२. समाचार पत्र के बारे में आप के विचार व सुझाव आमंत्रित है।

३. नियमित पाठक बनने के लिए आपके द्वारा समाचार पत्र की सदस्यता ग्रहण करना प्रार्थनीय है।

४. व्यक्तिगत एवं व्यापारिक संस्थानो के तथा अन्य विज्ञापन आमंत्रित है।

सम्पादक

दैनिक इंडिया वार्ता

कार्यालय : मोहकमपुर खुर्द नियर आई आई पी हरिद्वार रोड देहरादून।

दूरभाषः 7500581414,9359555222

एनएसडीसी इंटरनेशनल केयरगिवर्स को प्रशिक्षण प्रदान कर दे रहा विश्वस्तरीय अवसर

देहरादून, इंडिया वार्ता ब्यूरो। एनएसडीसी इंटरनेशनल दुनिया भर में केयरगिविंग सेगमेन्ट में कौशल की खामियों को दूर करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है, एनएसडीसी इंटरनेशनल ने ग्लोबल हेल्थकेयर की क्षमता बढ़ाने के लिए तकरीबन 1 लाख केयरगिवर्स को प्रशिक्षित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। गौरतलब है कि दुनिया भर में इन प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है।

अब तक संगठन हज़ारों कुशल केयरगिवर्स को जर्मनी, जापान, यूके और इज़रायल जैसे देशों में नौकरियों के अवसर उपलब्ध करा चुका है। इस प्रशिक्षण के तहत उम्मीदवारों को विशेष सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण तथा अंग्रेज़ी, जर्मन एवं जापानी भाषाओं में कौशल प्रदान किया गया है। ताकि उनकी रोज़गार क्षमता बढ़े और वे दुनिया के विभिन्न कोनों में अस्पतालों एवं चिकित्सा संस्थानों में नौकरी पाकर अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें।

हाल ही में कुछ प्रमुख जापानी एवं जर्मन कंपनियों ने एनएसडीसी इंटरनेशनल (एनएसडीसी की पूर्ण स्वामित्व की सब्सिडरी) के उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन के साथ नौकरी दी थी, जो संगठन द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता को दर्शाता है। आलोक कुमार, सीईओ, एनएसडीसी इंटरनेशनल ने कहा, आज पूरी दुनिया एसडीजी-3 के अनुरूप स्वास्थ्य एवं कल्याण के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में प्रयासरत है। इसी के मद्देनज़र एनएसडीसी इंटरनेशनल में हम हर संभव कोशिश कर रहे है। हम न सिर्फ अनुकूल प्रोग्राम लेकर आए हैं बल्कि उम्मीदवारों को उद्योग जगत की आवश्यकतानुसार कौशल प्रदान करने के लिए देशी-विदेशी संस्थानों के साथ साझेदारी भी की है। ताकि हम हेल्थकेयर की चुनौतियों को दूर करने में योगदान दे सकें। हमने दुनिया भर में हज़ारों कुशल केयरगिवर्स को नौकरी हासिल करने में मदद की है। अपने प्रयासों के द्वारा हम हेल्थकेयर सिस्टम में कुशल प्रोफेशनल्स को शामिल करने के लिए निरंतर अग्रसर हैं।'